

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी- श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या- 52/2014

बउनवान

सरकार जयें तहसीलदार, मांगरोल जिला-बारां

(प्रार्थी)

बनाम

1. छगनलाल
2. चतरभुज पुत्रगण सुखदेव
3. रामकन्या पुत्री सुखदेव जातिगण गूजर निवासीगण मालबमोरी तह० मांगरोल
(अप्रार्थीगण)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-82 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-1. परोकार सरकार

(प्रार्थी)

2. श्री बाबूलाल जैन अभिभाषक

(अप्रार्थीगण)

आदेश दिनांक- 03.03.2022



1- प्रार्थी सरकार जयें तहसीलदार, मांगरोल ने रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में अप्रार्थीगण के खाते विवादित आराजी ख०नं० 853 रकबा 0.29 है. किस्म माल 1 वाके ग्राम मालबमोरी तहसील-मांगरोल राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2067-70 खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट अवधि 2014-2023 में खसरा नम्बर 352 मि. रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई रहे है, वर्तमान सेटलमेंट संवत् 2044-63 में भू प्रबंध विभम्प द्वारा नवीन खसरा नंबर 853 रकबा 0.29 हैं कायम किये जाकर उक्त भूमि गै.मु.तलाई की किस्म माल 1 दर्ज कर ख.नं. 853 रकबा 0.29 है. को अवैधानिक रूप से अप्रार्थीगण के खाते दर्ज कर दिया। उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 की धारा-16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है। इसलिये अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन/नियमन नियम विरुद्ध है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों/नियमनो को विधि विरुद्ध करते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

अतः उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-16 के तहत अवैधानिक है तथा डी०बी० सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004

**जिला कलक्टर
बारां (राज०)**

अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन/नियमन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2- प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जर्ये अभिभाषक मदवार जवाब इस आशय का पेश किया कि मद नं. 1 जिस तरह लिखी गई है, स्वीकार नहीं है। इस मद में जो खसरा नंबर लिखे गये हैं वह रेफरेंस करने योग्य नहीं हैं। क्योंकि इस मद में जो तथ्य अंकित किये हैं, वह सर्वथा गलत हैं। मद नं. 2 अस्वीकार है। अब्दुल रहमान बनाम राज. सरकार के बिन्दु इस प्रकरण से नहीं मिलते हैं। मद नं. 3 अस्वीकार है। अतः निवेदन है कि तहसीलदार, मांगरोल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

3- उक्त जवाब प्राप्त होने पर हमने पत्रावली बहस हेतु नियत की।

4- हमने बहस उभयपक्ष सुनी। बहस के दौरान परोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि ग्राम मालबमोरी की आराजी साबिक खसरा नम्बर 352 मि. रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई को भू प्रबंध विभाग द्वारा दौराने सेटलमेंट कार्य अप्रार्थीगण के अवैधानिक रूप से खाते दर्ज कर दिया। जिस वक्त खाते दर्ज की गयी उस वक्त विवादित आराजी की किस्म गै.मु.तलाई थी, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। विवादित आराजी के बाद सेटलमेंट ख0नं0 853 रकबा 0.29 है. बने है जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। जिसकी किस्म माल 1 दर्ज है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य उपलब्ध नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आवंटन/नियमन नियम विरुद्ध हुआ है। ऐसे नियम विरुद्ध आवंटन/नियमन प्रारम्भतः ही शून्य है, जिसे किसी भी दशा में मान्यता नहीं दी जा सकती। वादग्रस्त आराजी के संबंध में जितनी भी कार्यवाहियाँ हुई है, वह निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत उक्त आराजी को गै.मु.तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा-82 भू राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

5- बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने परोकार सरकार के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 853 रकबा 0.29 है. वाके ग्राम मालबमोरी की किस्म माल 1 है जो तलाई के स्वरूप में स्थित नहीं है। विवादित आराजी वर्तमान में खाल नाल तलाई की श्रेणी में नहीं है ओर वर्तमान स्थिति में बिल्कुल समतल जमीन है जहां पर पानी का ठहराव नहीं है। विवादित आराजी वर्तमान में कृषि योग्य भूमि है। उक्त कार्यवाही प्राकृतिक



जिला कलक्टर
भारत (राज.)

न्याय के सिद्धान्तों से बाहर जाकर की है अप्रार्थीगण भूमिहीन काश्तकार है उक्त आराजी के अतिरिक्त अप्रार्थीगण के पास अन्य कोई आराजी जीवन यापन के लिये नहीं है। अतः उक्त रेफरेन्स खारिज फरमाया जावे।

साथ ही निवेदन किया कि तहसीलदार, मांगरोल द्वारा 35 वर्ष से अधिक समय पश्चात् अब्दुल रहमान बनाम सरकार रिट में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 के आधार पर उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किये जाने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है जबकि उक्त आवंटन/नियमन सरकार द्वारा किया गया है जिसमें स्टेट की ओर से तहसीलदार द्वारा रिप्रजेन्ट किया गया है। इसलिये तहसीलदार को उक्त कार्यवाही प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है।

6- हमने पेंरोकार सरकार व अप्रार्थीगण अभिभाषक की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि सेटलमेंट पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2014-23 अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 352 मि. रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई खाता सरकार दर्ज है। जिसका अप्रार्थी को आवंटन/नियमन किया गया है। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट संवत् 2044-63 नये खसरा नम्बर 853 रकबा 0.29 हैं बने है, जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार अप्रार्थीगण को जिस वक्त भूमि आवंटित/नियमन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म गै.मु.तलाई खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। अप्रार्थीगण को उक्त आराजी का आवंटन/नियमन नियम विरुद्ध हुआ है।

7- अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि अप्रार्थी को आवंटित/नियमन आराजी खसरा नम्बर 352 मि. रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई का आवंटन/नियमन की गयी आराजी के बाद सेटलमेंट संवत् 2044-63 नये खसरा नम्बर 853 रकबा 0.29 है 0 बने है। उक्त आराजी वास्तविक रूप से सेटलमेंट पूर्व किस्म गै.मु. तलाई दर्ज थी जिसका आवंटन अप्रार्थीगण को विधि विरुद्ध हुआ है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन को विधि विरुद्ध मानते हुए, आवंटन निरस्त करने के लिये रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्राषेत किया जाना उचित समझते है।

8- परिणास्वरूप, प्रार्थी जयें तहसीलदार, मांगरोल का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थीगण के वर्तमान में वाके ग्राम मालबमोरी में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 853 रकबा 0.29 है 0 किस्म माल 1, जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर 352 मि. रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई से बना है जिसका अप्रार्थीगण को गलत रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान,



जिला कलेक्टर
जायपुर (रकबा)

अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

9- तहसीलदार, मांगरोल को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटित/नियमन आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंस होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें। अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय होने तक, वर्णित आराजी खसरा नम्बर 853 रकबा 0.29 है० किस्म माल 1 वाके ग्राम मालबमोरी तहसील-मांगरोल की यथास्थिति बनाये रखें। इस आराजी को रहन, बेचान, हस्तान्तरण व खुर्द-बुर्द नहीं करे।

आदेश आज दिनांक 03.03.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।



(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारा
बारा (राज०)